साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 02 | अंक - 298 | जौनपुर, गुरूवार, 25 जुलाई 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

यूपी में नौ आईएएस, पांच पीसीएस अफसरों के तबादले

लखनऊ, संवाददाता। यूपी में नौ आईएएस व पांच पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। कानपुर नगर और फिरोजबाद के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) बदले गए हैं। आईएएस सुधीर कुमार नगर आयुक्त कानपुर नगर बनाया गया है वो अभी तक सीडीओ कानपुर नगर थे। आईएएस दीक्षा जैन सीडीओ कानपुर नगर बनाया गया है अभी तक वह सीडीओ फिरोजबाद थीं। आईएएस शत्रुघ्न बैश्य सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर नगर को सीडीओ फिरोजाबाद बनाया गया है। आईएएस प्रेरणा सिंह को ग्रेटर नोएडा अथारिटी की एसीईओ नियुक्त किया गया है। इसी तरह आईएएस शिव प्रसाद को प्रबन्ध निदेशक अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम बनाया गया है वह अभी तक विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के पद पर कार्यरत थे। आईएएस डॉ कंचन शरण अपर आयुक्त अलीगढ़ मंडल को अपर आयुक्त आगरा मंडल बनाया गया है। आईएएस अरुण कुमार अपर आयुक्त बरेली मंडल को अपर आयुक्त अलीगढ़ मंडल बनाया गया है। इसी तरह शीलधर सिंह यादव अपर आयुक्त लखनऊ मंडल को विशेष सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस रणविजय यादव अपर आयुक्त लखनऊ मंडल को विशेष सचिव सिंचाई विभाग नियुक्त किया गया है।

बेसिक शिक्षकों का निदेशालय घेराव स्थगित

लखनऊ, संवाददाता। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस समेत अन्य मांगों को लेकर 29 जुलाई को निदेशालय घेराव का निर्णय फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। शिक्षकों ने इस मामले में जल्द कमेटी के गठन और उसकी रिपोर्ट देने की मांग की है। साथ ही रिपोर्ट न आने तक डिजिटल अटेंडेंस न लगाने न ही प्रार्थना सभा की सेल्फी भेजने का पूर्व का निर्णय बरकरार रहेगा। प्रदेश में आठ जुलाई से परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस लगाने का निर्देश जारी हुआ था। इसे लेकर शिक्षकों ने पूरे प्रदेश में धरना, विरोध-प्रदर्शन किया था। साथ ही शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया था। इस बीच कुछ शिक्षक संगठनों की मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व संयुक्त मोर्चा की महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के साथ बैठक हुई थी। इसमें डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने, एक कमेटी के गठन और शिक्षकों की अन्य मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की बात कही गई थी। हालांकि संयुक्त मोर्चा 29 जुलाई को निदेशालय घेराव पर अड़ा हुआ था।

यह बजट मजबूत भारत और विकसित जम्मू की नींव रखेगा - मनोज सिन्हा

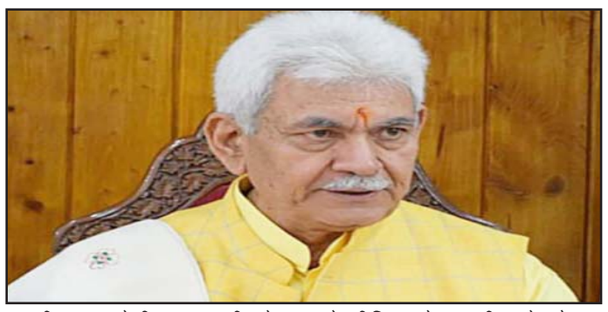

श्रीनगर, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले वित्त वर्ष 2024-25 का बजट संसद में पेश हो चुका है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि यह विकसित भारत और जम्मू-कश्मीर के लिए एक ऐतिहासिक बजट है। मनोज सिन्हा ने बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी और वित्त मंत्री का हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने विकसित भारत के लिए एक ऐतिहासिक बजट संसद में पेश किया है। विकसित भारत की मजबूत बुनियाद के अलावा यह विकसित जम्मू की भी नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि किसान, महिला, युवा और गरीब, ये समाज के चार मुख्य तपके हैं। ये सभी बजट के केंद्र बिंदु रहे हैं। किसानों को कैसे ऑर्गेनिक खेती के जरिए लाभ पहुंचे और खेती की लागत कम हो। युवाओं को कैसे रोजगार मिले, महिलाओं का सशक्तिकरण कैसे किया जाए, बजट में इन सब अहम मुद्दों पर जोर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देकर रोजगार को प्रोत्साहन दिया है। जम्मू कश्मीर के चौमुखी विकास के लिए भी केंद्र सरकार ने बजट आवंटित किया है। बजट पारित होने के बाद एक-एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे।

अपनी तहसील में ही निवास करें उपजिलाधिकारी और तहसीलदार

लखनऊ, संवाददाता। जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए योगी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। गुड गवर्नेंस की अपनी प्रतिबद्धता का अनुकरण करते हुए सरकार ने प्रदेश भर की विभिन्न तहसीलों में तैनात उपजिलाधिकारी (एसडीएम) एवं तहसीलदार को अब उसी तहसील में निवास करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य यह है कि उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार ज्यादा से ज्यादा समय अपनी तहसील में बिताएं एवं जनसामान्य की समस्याओं को सुनकर निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत उसका निराकरण करने का प्रयास करें। इससे न सिर्फ अधिकारियों की, बल्कि सरकार की छवि में भी सुधार होगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को

इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आकस्मिक जांच की जाएगी

मुख्य सचिव की ओर से मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को जो निर्देश दिए गए हैं, उसके अनुसार जनसमस्याओं का ससमय निराकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता व तत्परता से कार्य करें। इस निर्देशन व पर्यवेक्षण को सशक्त बनाने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित तहसीलदार एवं उपजिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात हैं, वहीं निवास करें। तहसील राजस्व प्रशासन के अंतर्गत सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरह हो, यह सुनिश्चित करना संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण का प्राथमिक दायित्व है। संबंधित जिलाधिकारी व मंडलायुक्तगण यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित तहसीलदार व उप जिलाधिकारी जिस तहसील में तैनात किए गए हैं, वहीं निवास करें।

बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल पास

बिहार, एजेसी। पेपर लीक और धांधली पर अंकुश लगाने के लिए नीतीश कुमार सरकार ने बुधवार को विधानसभा में बिहार सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2024 पेश किया। दोषियों के लिए तीन से दस साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान किया गया है कि पेपर लीक या उससे जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल लोग इस कानून के तहत दोषी होंगे। आरोपी को 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना होगा। इस कानून के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। इस कानून से अभ्यर्थियों और छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। कानून में अपराधियों के लिए 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रस्ताव है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज

विपक्ष की परिभाषा बदल गयी है। सरकार अच्छा काम भी करती है तो विपक्ष विरोध करता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पेपर लीक विरोधी विधेयक पारित होने के खिलाफ विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक मामले में ताजा घटनाक्रम में, सीबीआई ने नीट-पीजी पेपर लीक मामले में एम्स पटना के चार एमबीबीएस छात्रों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने मुख्य आरोपी पंकज कुमार उर्फ आदित्य को भी गिरफ्तार किया है, जो जमशेदपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के 2017 बैच के सिविल इंजीनियर हैं, उन्होंने हजारीबाग में एनटीए के ट्रंक से एनईईटी-यूजी पेपर चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि बोकारो निवासी कुमार को पटना से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि एजेंसी ने पेपर चुराने में कुमार की मदद करने के आरोप में सिंह को भी हजारीबाग से गिरफ्तार किया। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने छह एफआईआर दर्ज की हैं। बिहार की एफआईआर पेपर लीक से संबंधित है, जबकि गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र की शेष एफआईआर उम्मीदवारों के प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के संबंध में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संदर्भ पर एजेंसी की अपनी एफआईआर नीट-पीजी 2024 में कथित अनियमितताओं की व्यापक जांच से संबंधित है।

करीब 20 हजार करोड़ से यूपी में बदलेगी रेल की तस्वीर

लखनऊ, संवाददाता। उत्तर रेलवे में नई रेलवे लाइनों को बिछाने, सेफ्टी बेहतर करने, रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन व यात्री सुविधाओं आदि की वृद्धि के लिए 19,848 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यह यूपीए सरकार के दस वर्षों के कार्यकाल के बजट की तुलना में 18 गुना अधिक है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित प्रेसवार्ता में दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के डीआरएम सचिंद्र मोहन शर्मा व पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम आदित्य कुमार जुड़े रहे। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे को कुल 2.62 लाख करोड़ रुपये का बजट दिया गया है, इसमें 1.08 करोड़ रुपये सेफ्टी के मद में दिया गया है। वर्ष 2004-14 तक के दस वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को औसतन 1109 करोड़ रुपये दिए जाते रहे हैं। वहीं वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश में रेलवे के डेवलपमेंट के लिए 19,848 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जोकि यूपीए सरकार की तुलना में 18 गुना है। रेलमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में रेलवे का विद्युतीकरण शतप्रतिशत हो गया है। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों के विकास से लेकर ट्रैक मेंटीनेंस आदि के 92 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाएं चल रही हैं, जिसके लिए भी पैसा दिया गया है। 157 अमृत भारत स्टेशनों का प्रदेश में विकास किया जा रहा है। पिछले दस वर्षों में 1490 आरओबी-आरयूबी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं 490 किमी रेलवे ट्रैक का निर्माण प्रतिवर्ष किया गया है। इस लिहाज से दस वर्षों में 4900 किमी ट्रैक बनाया गया है, जबकि स्विट्जरलैंड में रेलवे का कुल नेटवर्क ही पांच हजार किमी का है।

छत्तीसगढ़ सरकार की जवाबदेही तय कराने का समय आ गया - पायलट

रायपुर, एजेसी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के चुनाव प्रभारी सचिन पायलट ने विष्णु देव साय सरकार पर बुधवार को हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ चुनाव प्रभारी एवं दिग्गज कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा सरकार पर राज्य में अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, 5 साल की सरकार में हम लोगों ने जो कानून और नियम बनाए थे, भाजपा सरकार ने उसको खत्म कर जनता के साथ अन्याय करने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा, राज्य में पिछले 6-7 महीनों में जो हत्याएं, बलात्कार हो रहे हैं और जो गोलियां चल रही हैं।

नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट फैसला स्वागत योग्य, सत्यमेव जयते - धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली, एजेसी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट की दोबारा परीक्षा कराने से इनकार कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सत्यमेव जयते। उन्होंने कहा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। हमारी प्राथमिकता देश के विद्यार्थी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसी बात को सबसे ऊपर रखा है। दो ढाई महीने से सरकार के पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट ने नो री-नीट की बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए परीक्षा लीक के खिलाफ सख्त कानून बनाया है। हमने उच्च स्तरीय कमेटी की भी घोषणा की जिसके चेयरमैन प्रो. राधा कृष्णन है। वे सभी के सुझाव को सुन रहे हैं और इसका जल्द ही रिपोर्ट आएगा। एनटीए को जीरो टेंपर फ्री संस्था बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हमें एनटीए को एक पारदर्शी, शून्य-त्रुटि वाली संस्था बनाना है। इसके लिए जो भी तकनीक और वैश्विक प्रथाओं को अपनाने की

आवश्यकता है, हम अपनाएंगे। जो अव्यवस्था हुई है, उसके लिए किसी को नहीं छोड़ा जाएगा और सीबीआई अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अदालत ने कुछ सुझाव दिया है और जल्द ही एनटीए फाइनल रिजल्ट जारी करेगी। जब से एनटीए शुरू हुआ है, गरीब वंचित और पिछड़े लोगों की संख्या बढ़ी है लेकिन, कुछ लोग तथ्य को नहीं जानते और इसे अमीरों की व्यवस्था कहते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट के बार-बार कहने के बाद भी नीट का विरोध कर रहे हैं। जबकि नीट में पिछली बार तमिलनाडु से टॉपर थी। जब इसे पारित किया गया तो विपक्षी सत्ता में थे और तमिलनाडु के ये दल उनके सहयोगी थे। अगले एक दो दिन में नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा नीट-यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा पर आज का फैसला अटकलों पर विराम लगाएगा और लाखों मेहनती और ईमानदार छात्रों को राहत की सांस देगा। छात्रों के हित को बरकरार रखने वाले ऐतिहासिक फैसले के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आभारी हूं। उन्होंने आगे लिखा यह फैसला उन लोगों की आंखें खोल देगा, जिन्होंने भारतीय परीक्षा प्रणाली को बकवास बताया और निहित स्वार्थों और राजनीतिक लाभ के लिए इस अवसर का फायदा उठाने के साथ नागरिक अशांति और अराजकता को बढ़ावा दिया।

ममता ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ का रुख कर एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया है। एकल पीठ ने बनर्जी और तीन अन्य पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ "मानहानिकारक और गलत" बयान देने पर रोक लगा दी थी। बनर्जी के वकील एस.एन. मुखर्जी ने न्यायमूर्ति आई.पी. मुखर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष कहा कि बनर्जी ने राज्यपाल के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। वकील ने कहा कि उनकी जिस टिप्पणी की बात हो रही है वह दो नवनिर्वाचित विधायकों के शपथ ग्रहण के संबंध में सार्वजनिक दायित्व निभाने से जुड़ी है। मुखर्जी ने कहा कि बोस ने समाचारों का हवाला दिया है, लेकिन उन्होंने मानहानि मामले में प्रकाशनों को पक्षकार नहीं बनाया है। पीठ ने कहा कि मामले पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी जब बोस के वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने तृणमूल कांग्रेस के दो नवनिर्वाचित विधायकों सयंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार के शपथ ग्रहण पर विवाद से संबंधित एक प्रशासनिक बैठक के दौरान कुछ टिप्पणी करने के लिए बनर्जी और तीन अन्य के खिलाफ राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर 16 जुलाई को अंतरिम आदेश पारित किया था। पीठ ने उनपर रोक लगाने का आदेश पारित किया था, जो 14 अगस्त तक लागू रहेगा। यह आदेश दो विधायकों और टीएमसी नेता कुणाल घोष पर भी लागू होगा।

बजट समावेशी विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण - जेपी नड्डा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को समावेशी बताते हुए इसकी

तारीफ की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सदन में आम बजट पेश किया। जे.पी. नड्डा ने कहा कि 2024-25 का पूर्ण बजट समावेशी विकास, सतत विकास और आर्थिक लचीलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह दूरदर्शी बजट न केवल राष्ट्र की तात्कालिक जरूरतों पर ध्यान देता है, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी नवाचार और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए दीर्घकालिक समृद्धि के लिए एक मजबूत रूपरेखा भी तैयार करता है। उन्होंने कहा, ष्यह बजट अधिक समृद्ध और समतावादी भारत का मार्ग प्रशस्त करता है। बजट, दूरदर्शी नीतियां और रणनीतिक निवेश विकास को गति देने, रोजगार सृजित करने और सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हैं। यह बजट गतिशील और आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भाजपा अध्यक्ष ने गांव, गरीब, महिला, युवा, दलित और आदिवासी पर केंद्रित बजट देने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, यह बजट समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। यह आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की बात करता है। यह दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी चुनौतियों से निपटने में कितनी सक्षम है। केंद्रीय गृह अमित शाह ने कहा, ष्बजट 2024-25 मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के देशवासियों की आशा, आकांक्षा और विश्वास पूर्ति के संकल्प का प्रतिबिम्ब है। यह युवाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ-साथ किसानों के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाकर विकसित तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस बजट के माध्यम से देश की भावी पीढ़ी के आत्मबल को मजबूती देने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं।

देश को सबसे ज्यादा खनिज संपदा देने वाले झारखंड के लिए बजट में कुछ भी नहीं - हेमंत

रांची, एजेंसी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय बजट पर संक्षिप्त प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि यह देखना होगा कि झारखंड को वे कितना दे रहे हैं और इसके बदले में झारखंड से कितना ले रहे हैं? सोरेन ने कहा कि वे पूरी जानकारी लेने के बाद केंद्रीय बजट पर अपनी राय रखेंगे। वहीं, हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, देश की 60 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और किसानों का हाल देखिए..., अरबपति मित्रों को अरबों-अरब की छूट और देश के अन्नदाताओं के बजट की लूट। उन्हें सिर्फ और सिर्फ चुनावों से मतलब है। झामुमो के प्रवक्ता और केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि

इसमें नौकरी की आस लगाए बैठे युवाओं को मायूसी हाथ लगी है। उन्हें अप्रेंटिसशिप देने के नाम पर झुनझुना थमाया गया है। महंगाई के नियंत्रण पर कोई बात नहीं की गई है। देश को सबसे ज्यादा खनिज संपदा देने वाले झारखंड के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आंध्रप्रदेश और बिहार के मिडिल क्लास के लोग जो थोड़ी-बहुत बचत करते थे, उन्हें भी हतोत्साहित किया गया है। यही वजह है कि बजट पेश होते ही सेंसेक्स नीचे गिर गया।

संपादकीय

एक प्रशंसनीय बजट

बजट केंद्र सरकार की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण होता है। आम तौर पर, इससे ज़्यादा और इससे कम कुछ नहीं होता। ऐतिहासिक रूप से, हम करों में अपेक्षित वार्षिक परिवर्तनों के कारण बजट के प्रति आसक्त रहे हैं, मुख्य रूप से, हालांकि विशेष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष करों के कारण। (जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनके लिए बजट से पहले सिगरेट हमेशा गायब हो जाती थी, और नए मूल्य टैग के साथ फिर से सामने आती थी)। हम माल और सेवा कर के बारे में शिकायत कर सकते हैं, जो अभी भी प्रगति पर है। बहुत सारी दरें। बहुत ज़्यादा विभेद। मुकदमेबाजी और वर्गीकरण विवाद। हर वस्तु या सेवा जीएसटी का हिस्सा नहीं है (पेट्रोलियम और संबंधित उत्पाद, शराब, तंबाकू, अचल संपत्ति)। औसत कर दर जो राजस्व तटस्थ दर मानी जाती थी, उससे कम है। इन खामियों और दोषों के बावजूद, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जीएसटी पिछली प्रणाली (उदाहरण के लिए, बजट भाषण का पैराग्राफ 115) की तुलना में एक अभूतपूर्व सफलता रही है और जीएसटी परिषद भी संघ–राज्य निर्णय लेने में सफलता का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। ऐसा होने पर, अप्रत्यक्ष कर बजट के दायरे से बाहर हो जाते हैं। ये बदलाव होंगे, लेकिन बजट के बाहर और जीएसटी परिषद के जरिए। इस मामले में, बजट अपनी रहस्यपूर्णता और रहस्य को कुछ हद तक खो देता है, जैसा कि होना चाहिए। सभी अप्रत्यक्ष कर नहीं, कम से कम अभी तक नहीं। आयात शुल्क हैं। अधिकांश अर्थशास्त्री (सभी नहीं) तर्क देंगे कि प्रतिस्पर्धी होने के लिए, भारत को बुनियादी सीमा शुल्क कम करने की आवश्यकता है। एक आदर्श टैरिफ संरचना में, कच्चे माल पर मध्यवर्ती वस्तुओं की तुलना में कम शुल्क होना चाहिए और मध्यवर्ती वस्तुओं पर तैयार माल की तुलना में कम शुल्क होना चाहिए। समस्या यह पता लगाने में है कि कच्चा माल क्या है, मध्यवर्ती क्या है और तैयार माल क्या है। समस्या को और जटिल बनाने के लिए, सभी ज्ज् सदस्यों पर सबसे पसंदीदा राष्ट्र दरें लागू होती हैं और उन देशों के लिए विशेष टैरिफ होते हैं जिनके साथ क्षेत्रीय व्यापार समझौते होते हैं। नतीजतन, संरक्षण की प्रभावी दरें विकृत हो जाती हैं और एक उलटा शुल्क ढांचा होता है। बेशक, समस्या मौजूद है। क्या किसी को जल्दबाजी में इसके बारे में कुछ करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि बजट हाथ में है? वित्त मंत्री ने कहा है (बजट भाषण का पैरा 117) कि अगले छह महीनों में एक व्यापक समीक्षा की जाएगी। अगर हमने इतना लंबा इंतजार किया है, तो मुझे नहीं लगता कि छह महीने कोई बड़ी बात है। (बजट में सीमा शुल्क में कुछ मामूली बदलाव हैं।) हालाँकि, प्रत्यक्ष कर भी हैं, व्यक्तिगत आय और कॉर्पोरेट। बजट भाषण का इंतजार करते हुए, ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये बदलाव हैं। लेकिन वहाँ एक बड़ी तस्वीर है। हम एक सरलीकृत प्रणाली में जाना चाहते हैं जहाँ कोई छूट न हो और जहाँ कर की दरें साल–दर–साल न बदलें। छूट चार्टर्ड अकाउंटेंट और वकीलों को समृद्ध बनाती है और अनुपालन लागत बढ़ाती है। यही कारण है कि आयकर रिटर्न जमा करने वाले बहुत से लोग शून्य कर योग्य आय घोषित करते हैं। (कृषि आय पर कर लगाना राज्य का विषय है।) यह कर से बचने (वैध छूट का लाभ उठाना) है, कर चोरी नहीं। हमारे पास पहले से ही दो चौनल हैं, एक कम (शून्य नहीं) छूट वाला और दूसरा मौजूदा छूट वाला।

व्यक्तिगत आयकर और कॉर्पोरेट कराधान दोनों के लिए, मैं इनमें से किसी एक चौनल को चुन सकता हूँ। बजट (बजट भाषण का पैरा 136) हमें बताता है कि कॉर्पोरेट कर संग्रह का 58: सरलीकृत व्यवस्था से आया है और दो तिहाई से अधिक व्यक्तिगत आयकरदाता भी नई व्यवस्था में चले गए हैं। आदर्श रूप से, छूट–रहित व्यवस्था में, व्यक्तिगत आय कराधान और कॉर्पोरेट कराधान के बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा। (असंगठित उद्यम व्यक्तिगत आय कर का भुगतान करते हैं।) हम कुछ समय से प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के पूर्ण बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। बजट में (बजट भाषण का पैरा 137) अगले छह महीनों में आयकर अधिनियम की व्यापक समीक्षा का वादा किया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रत्यक्ष कर में बदलाव मानक कटौती और स्लैब (व्यक्तिगत आय कराधान के लिए), मुकदमेबाजी और अपील में कमी और पूंजीगत लाभ पर कराधान तक सीमित हैं। जबकि मैं उन कारणों को समझ सकता हूँ कि इन दरों को क्यों बढ़ाया गया, मैं पूरी तरह से सहानुभूति नहीं रख सकता। (मुझे संदेह है कि अचल संपत्ति के लिए सूचकांक की कमी एक खंड है जिसकी समीक्षा की जाएगी।) जैसे–जैसे कोई करों से दूर होता जाता है, गैर–कर राजस्व और व्यय होता है। गैर–कर राजस्व मुख्य रूप से विनिवेशधनिजीकरण प्राप्तियों के रूप में रहा है। निजीकरण के विपरीत सार्वजनिक संपत्तियों के मुद्रीकरण पर जोर देने के साथ, कोई भी समझ सकता है कि विनिवेश प्राप्तियों को रूढ़िवादी 78,000 करोड़ रुपये पर क्यों पेश किया जाता है। राजस्व व्यय अल्पावधि में तय होता है। न केवल वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान, बल्कि सब्सिडी भी। हर अर्थशास्त्री तर्क देगा कि पूंजीगत व्यय (सरकार द्वारा) राजस्व व्यय से बेहतर है। विशेष रूप से कोविड के दौरान, पश्चिम के कई देशों के विपरीत, भारत पूंजीगत व्यय (बुनियादी ढांचे को पढ़ें) पर टिका रहा। इससे अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता में वृद्धि होती है और 2024–25 में, पूंजीगत व्यय (बजट भाषण का पैरा 79) जीडीपी का 3.4: होगा। यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए।

भारत में तेजी से हो रहा है वित्तीय समावेशन

आदित्य

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक एवं पेन्शन क्षेत्र के हितधारकों को शामिल करते हुए वित्तीय समावेशन सूचकांक विकसित किया है। दरअसल, भारत में विभिन्न क्षेत्रों में हो रही अतुलनीय प्रगति को दर्शाने के लिए अब अपने सूचकांक विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है क्योंकि वैश्विक स्तर पर वित्तीय एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्यरत विदेशी संस्थानों द्वारा विकसित किए गए सूचकांकों के आधार पर किए जाने वाले सर्वे में तो विभिन्न क्षेत्रों में भारत की प्रभावशाली प्रगति की सही तस्वीर पेश नहीं की जा रही है। इन सूचकांकों के आधार पर किए गए कई सर्वे में तो आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देते हैं। जैसे, एक सर्वे में भुखमरी के क्षेत्र में भारत की स्थिति को अफ्रीकी देशों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बंगलादेश से भी बदतर बताया गया था।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किए गए वित्तीय समावेशन सूचकांक के आधार पर मार्च 2024 के परिणाम हाल ही में जारी किए गए हैं। इन परिणामों के अनुसार, भारत में वित्तीय समावेशन मार्च 2017 में 43.4, मार्च 2021 में 53.9 एवं मार्च 2023 में 60.1 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 प्रतिशत हो गया है। यह सूचकांक भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई अतुलनीय एवं स्थिर प्रगति को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया यह सूचकांक वित्तीय समावेशन के विभिन्न आयामों (नागरिकों की वित्तीय संस्थानों पर बढ़ती पहुंच, वित्तीय उत्पादों का बढ़ता उपयोग एवं वित्तीय सेवाओं की गुणवत्ता) पर देश में वित्तीय समावेशन के संदर्भ में जानकारी को 0 से 100 तक के मान में बताता है। यदि मान कम है तो देश में वित्तीय समावेशन भी कम है और इसके विपरीत यदि मान अधिक है तो देश में वित्तीय समावेशन भी अधिक है। भारत में यह मान मार्च 2024 में बढ़कर 64.2 प्रतिशत हो गया है। उक्त वर्णित तीन आयामों में कई पैरामीटर शामिल हैं, इनका मूल्यांकन 97 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। इस कार्यप्रणाली के कारण ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विकसित किया गया यह सूचकांक वित्तीय समावेशन का एक व्यापक संकेतक बन गया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है।

किसी भी देश में वित्तीय समावेशन के बढ़ने का आशय यह है कि उस देश के नागरिकों की उस देश के बैकिंग संस्थानों तक पहुंच बढ़ रही है और यह उस देश की अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। वर्ष 2014 में भारत में प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत विभिन्न बैंकों में गरीब वर्ग के जमा खाते खोलकर उन्हें वित्तीय समावेशन का हिस्सा बना लिया गया था। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 52 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं एवं इन जमा खातों में लगभग 2.35 लाख करोड़ रुपए की राशि जमा है। केंद्र एवं विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा देश के गरीब वर्ग को दी जाने वाली सहायताध्प्रोत्साहन राशि को भी इन खातों में आज सीधे ही जमा कर दिया जाता है, इसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के रूप में भी जाना जाता है, जिससे इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार लगभग समाप्त हो गया है क्योंकि इससे अंततः लीकेज कम हुए है और यह सुनिश्चित हुआ है कि योजनाओं का लाभ अंतिम लाभार्थी तक सीधे ही पहुंचे। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के दूर दराज के इलाकों में निवासरत नागरिकों को बैंकिंग, बचत और जमा खाते, राशि हस्तांतरण, ऋण, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं को उपलब्ध कराना था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रधानमंत्री जनधन योजना

पूर्ण रूप से सफल रही है और भारत में वित्तीय समावेशन को अगले स्तर पर ले जाने में भी सहायक रही है। साथ ही, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए जमा खातों को भारत की विशिष्ट पहचान प्रणाली (आधार कार्ड) से जोड़कर, केंद्र सरकार ने देश में वित्तीय लेन देन प्रणाली को सुव्यवस्थित कर लिया है एवं बैकिंग व्यवहारों में धोखाधड़ी की सम्भावना को कम करने में भी सफलता अर्जित की है। आज भारत की प्रधानमंत्री जनधन योजना को पूरे विश्व में सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना के रूप में पहिचान मिली है। देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज भी वित्तीय समावेशन के मुख्य उपकरण के रूप में माना जा रहा है और इस योजना के अंतर्गत देश के नागरिकों के खाते विभिन्न बैंकों में उसी उत्साह से लगातार खोले जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी भारत के विभिन्न बैंकों में प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत लगभग 3.3 करोड़ नए जमा खाते खोले गए हैं इससे इस योजना के अंतर्गत खोले गए कुल खातों की संख्या बढ़कर 51.95 करोड़ हो गई है एवं इन जमा खातों में 234,997 करोड़ रुपए की राशि जमा हो गई है। अब देश का एक गरीब नागरिक भी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। वित्तीय समावेशन के दायरे में लाए गए नागरिक वित्तीय क्षेत्र में साक्षर होने के पश्चात अब तो भारत के पूंजी बाजार (शेयर बाजार) में भी अपना निवेश करने लगे हैं एवं उनकी विभिन्न ऋण योजनाओं एवं बीमा उत्पादों तक पहुंच भी बढ़ गई है। वित्तीय सेवाओं तक इस पहुंच ने देश के नागरिकों को आर्थिक रूप से बहुत सशक्त बना दिया है, इससे अंततः यह नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं छोटे व्यवसायों में निवेश करने में सक्षम हुए हैं और इस प्रकार इन नागरिकों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हुआ है। भारत में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में हुई उक्त वर्णित अतुलनीय प्रगति की जानकारी हम आम नागरिकों को तभी मिल पा रही है जब भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में ही एक सूचकांक विकसित किया है। यदि वित्तीय समावेशन का सूचकांक किसी विदेशी संस्थान द्वारा तैयार किया जाता तो सम्भव है कि भारत की इस महान उपलब्धि को जानने से हम वंचित रह जाते। अब समय आ गया है कि इसी प्रकार के सूचकांक अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय वित्तीय एवं आर्थिक संस्थानों द्वारा ही तैयार किए जाने चाहिए, ताकि हम आम नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में भारत की अतुलनीय प्रगति की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो सके।

गलियारे के दूसरी ओर से विचार उठाना

विनोद

इस अप्रैल में कांग्रेस द्वारा अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने के अगले दिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस दस्तावेज पर मुस्लिम लीग की छाप है। पता चला कि यह दस्तावेज मोदी के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एक ऐसे चुनाव में जहाँ भाजपा ने अपना बहुमत खो दिया, मतदाताओं का बड़ा संदेश थारू ष्मंदिर के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरी नौकरी कहाँ है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर गंभीरता से ध्यान दिया है। उन्होंने अपने बजट भाषण में श्रोजगारश शब्द का 24 बार उल्लेख किया, जबकि पिछले साल यह संख्या सिर्फ तीन बार थी, और रोजगार सृजन के लिए विशिष्ट नए विचारों की घोषणा की– रोजगार–संबंधी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना और इंटर्नशिप योजना। केवल, ये दोनों ही विचार कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में उल्लिखित थे जिन्हें मोदी सरकार ने अपनाया है। रोजगार जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर इस तरह की द्विदलीय सहमति प्रशंसनीय और बहुत जरूरी है। बजट सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से आर्थिक नीति की दिशा में बदलाव की आवश्यकता की स्वीकृति थी। रोजगार सृजन के लिए कॉर्पोरेट कर कटौती, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन या जीडीपी वृद्धि को बढ़ावा देने जैसे अप्रत्यक्ष प्रोत्साहनों की तुलना में अधिक प्रत्यक्ष प्रोत्साहन की आवश्यकता पहली स्वीकृति थी। दूसरी स्वीकृति मूर्खतापूर्ण आर्थिक राष्ट्रवाद को त्यागना और सीमा शुल्क को कम करके तथा चीन के साथ व्यापार का विस्तार करके मुक्त व्यापार को अपनाना था। जबकि ईएलआई और प्रशिक्षुता योजनाओं के विचार कांग्रेस के घोषणापत्र से लिए गए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया है। वित्त मंत्री ने अगले पांच वर्षों में रोजगार और कौशल योजनाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय की घोषणा की, ताकि 4 करोड़ युवा भारतीयों को कौशल प्रदान किया जा सके और उन्हें रोजगार प्रदान किया जा सके। आडंबर को एक तरफ रखते हुए, बजट अनुलग्नक में इन योजनाओं के जटिल और पेचीदा विवरण दिए गए हैं, जो रोजगार सृजन के लिए उन्हें लुभाने के बजाय कॉर्पोरेट्स को डराने के लिए डिजाइन किए गए प्रतीत होते हैं। कांग्रेस का डिजाइन एक सरल ईएलआई योजना थी, जो जीएसटी–पंजीकृत कंपनी द्वारा बनाई गई प्रत्येक नई औपचारिक नौकरी के लिए एक मानक प्रोत्साहन प्रदान करती थी। इसके बजाय, बजट ने वेतन और समय की बाध्यताओं के साथ एक महीने की वेतन सब्सिडी की एक जटिल संरचना की घोषणा की, जो कंपनियों के लिए कागजी कार्रवाई और अनुपालन बोझ बढ़ा सकती है। इसी तरह, कांग्रेस की अप्रेंटिसशिप योजना 25 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए एक साधारण ऑन–द–जॉब, एक वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थी, जिसमें वे किसी भी निजी या सरकारी कंपनी में शामिल हो सकते थे, जिसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक हो। इसके बजाय, वित्त मंत्री ने इसे श्शीर्ष 500श कंपनियों तक सीमित कर दिया है, जिनसे हर साल 4,000 प्रशिक्षुओं को लेने की उम्मीद की जाती है, जो अनुचित और अव्यवहारिक है। फिर से, इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप का विचार शक्तिशाली है, लेकिन डिजाइन नौकरशाही की उलझन में फंस गया लगता है। मोदी सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय को जारी रखा है, जिसमें लगभग एक–चौथाई व्यय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवंटित किया गया है। यह दो दशकों में सबसे अधिक है। जबकि बुनियादी ढांचा एक आवश्यक और उपयोगी प्रयास है, यह निजी निवेश को बाहर करने का जोखिम उठाता है, जो पिछले कुछ वर्षों से मामला रहा है। प्रत्यक्ष नकद सहायता या ऐसे अन्य उपायों के माध्यम से उपभोग मांग को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रत्यक्ष प्रयास नहीं किया गया। यदि कोई है, तो नई रोजगार योजनाओं के भुगतान के लिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कटौती की गई है, जो एक बड़ा जुआ है। दिलचस्प बात यह है कि राष्ट्रवादी कट्टरता के बावजूद रक्षा आवंटन में भी 2023–24 के संशोधित अनुमानों से थोड़ी कमी की गई है। कराधान, जो सरकार के बजट का आधार है, प्रतिगामी बना हुआ है, जिसमें एकमात्र प्रगतिशील घोषणा स्टार्ट–अप के लिए निवेश बाधाओं को दूर करने के लिए श्एंजेल टैक्सश को समाप्त करना है। दिलचस्प बात यह है कि यह भी कांग्रेस के घोषणापत्र का एक और वादा है जिसे वित्त मंत्री ने अपनाया है। प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष कर अनुपात 35:65 बना हुआ है, जो दुनिया की अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बिल्कुल विपरीत है। जीएसटी के सरलीकरण पर कोई प्रतिबद्धता नहीं थी, और मध्यम वर्ग और गरीबों की कीमत पर कॉरपोरेट्स को प्रोत्साहन और कम करों की बौछार जारी है। बजट ने सट्टा जुए को कम करने और बाजारों को ठंडा करने के लिए शेयर बाजार के लेन–देन के लिए करों में उचित वृद्धि की। अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक चिंता बाहरी क्षेत्र पर है, जहां 2023–24 में निर्यात में 3 प्रतिशत की कमी आई है। निर्यात वृद्धि के बिना भारत तेज गति से विकास नहीं कर सकता, जैसा कि यूपीए दशक ने साबित किया है। ऐसा लगता है कि बजट ने इसे मान्यता दी है और कुछ सीमा शुल्क वापस ले लिए हैं। आर्थिक सर्वेक्षण ने भी चीन के साथ व्यापार को अपनाने और बंद न होने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। ये स्वागत योग्य सुधार हैं, लेकिन शायद निर्यात वृद्धि को दोहरे अंकों में बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। बजट का सबसे टालने योग्य हिस्सा आंध्र प्रदेश और बिहार के दो राज्यों को खुश करना था, जिनके सत्तारूढ़ दलों के समर्थन पर मोदी सरकार टिकी हुई है। इन दो राज्यों के लिए भारी बजट आवंटन किया गया था, जो महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे अमीर राज्यों से आएगा। जब विपक्ष शासित राज्यों और केंद्र में मोदी सरकार के बीच पहले से ही विश्वास का गंभीर क्षरण हो रहा है।

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और मीडिया के उलझे रिश्ते

संजय

माननीय प्रधानमंत्री जी हम आभारी हैं कि आप हमारे बीच आए। मेरी ऑन दी जॉब लर्निंग अब शुरू हो गई है और 2024 तक मैं देश की सबसे अच्छी जर्नलिस्ट होने की कोशिश करूंगी। उम्मीद करती हूं कि तब आपसे एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का मौका मुझे मिलेगा। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।" ये शब्द हैं भारत की पहली एआई बॉट एंकर सना के। आर्टिफिशनल इंटेलिजेंस के मीडिया जगत में बढ़ते इस्तेमाल की कई संभावनाएं हैं। इसी में से एक है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री एक एआई एंकर से देश के भविष्य और योजनाओं के बारे में चर्चा करते दिखें। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्स्ट टू स्पीच फीचर की बदौलत अब भारतीय न्यूजरूम में मशीन को इंसानी चेहरे में ढालकर खबरें पेश की जा रही हैं। पिछले साल अप्रैल के महीने में इंडिया टुडे ग्रुप ने एआई एंकर से समाचार बुलेटिन का प्रसारण शुरू किया था। लॉन्च कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एंकर का परिचय देते हुए कहा गया था कि वह ब्राइट है, सुंदर है, उम्र का उन पर कोई असर नहीं होता है और न ही कोई थकान होती है, वो बहुत सारी भाषाओं में बात कर सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी दुनिया को फिर से परिभाषित करने, मानवीय क्षमता की सीमाओं को पार करने और अभूतपूर्व पैमाने पर उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को नया आकार देने के लिए तैयार है। मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में, एआई का आगमन कंटेंट क्रिएटर्स को सामग्री निर्माण के लिए शक्तिशाली उपकरणों से सशक्त बना रहा है, नए अनुभवों को अनलॉक कर रहा है और कलात्मक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों का उपभोग करने, बनाने और उनसे जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल रहा है। हाल के कुछ समय से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और पत्रकारिता का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह रहा है। मौजूदा समय में भारत की मेनस्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा विज्ञापन पर निर्भर होकर काम कर रहा है। ऐसे में तकनीक के जरिये डेटा के आधार पर समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करना और अन्य काम भी इंसान की जगह मशीन की बदौलत होने ने मीडिया इंडस्ट्री के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पत्रकारिता के भविष्य से लेकर पत्रकारिता करने वालों के भविष्य को लेकर भी संकट खड़ा होने की बात कही जा रही है। लेकिन एआई पत्रकारिता वास्तव में क्या है? क्या यह चिंता का एक विषय है या फिर सूचना जगत में एक ऐसी नई क्रांति है, जो पत्रकारिता के सही आयाम स्थापित करने में कामयाब हो पाएगी।

गैर–पश्चिमी देशों का दिलचस्प मामला

ललित

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साल की शुरुआत में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में अपने सह–पैनलिस्ट और अमेरिकी समकक्ष एंटनी एस ब्लिंकन के साथ बैठकर बोलते हुए भारत को "गैर–पश्चिम" कहा था, न कि "पश्चिम विरोधी"। दूसरी ओर, चीन–रूस गठबंधन ने स्पष्ट रूप से पश्चिम विरोधी मोर्चा संभाला है। रूस के राष्ट्रपति के रूप में अपने पांचवें कार्यकाल के लिए उद्घाटन के बाद, व्लादिमीर पुतिन ने अपनी "बिना सीमा" साझेदारी को मजबूत करने के लिए चीन की अपनी पहली विदेश यात्रा की। अपने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ जारी संयुक्त बयान में, मास्को और बीजिंग ने "एशिया–प्रशांत क्षेत्र में बंद संघों और ब्लॉक संरचनाओं के निर्माण के लिए अपना विरोध व्यक्त किया, विशेष रूप से, किसी भी तीसरे पक्ष के खिलाफ निर्देशित सैन्य गठबंधन और गठबंधन" विशेष रूप से "अमेरिका की "इंडो–पैसिफिक" रणनीति के क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव" को ध्यान में रखते हुए। हाल ही में, अपने 75वें वर्षगांठ शिखर सम्मेलन में, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) ने कहा, रूस और पीआरसी के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी और नियम–आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर करने और उसे नया आकार देने के उनके पारस्परिक रूप से मजबूत प्रयास, गहरी चिंता का कारण हैं। लगभग उसी समय, पश्चिमी देशों को काफी निराश करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मास्को में 22वें भारत–रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोस्ती का परिचय दिया। गैर–पश्चिमी और उसके अवतार प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा के आकर्षण के बावजूद, नई दिल्ली इस बात पर जोर देने के लिए उत्सुक है कि उसके द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव पश्चिम के विरुद्ध न हों। ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) और इसके नए सदस्यों और एससीओ (शंघाई सहयोग संगठन) जैसे समूहों में मूल्य खोजने के अलावा, भारत का पश्चिमी देशों और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक लगाव शानदार ढंग से बढ़ा है। भारत चीन द्वारा शुरू की गई क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी से बाहर रहा है और अमेरिका द्वारा शुरू की गई इंडो–पैसिफिक आर्थिक रूपरेखा में शामिल हो गया है। इसके अलावा, इंडो–पैसिफिक क्षेत्र की विकसित हो रही संरचना में, भारत चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता (क्वाड) के साथ है और "स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम–आधारित" इंडो–पैसिफिक के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुट है। जापान और ऑस्ट्रेलिया भी पश्चिम और गैर–पश्चिम द्वंद्व में दिलचस्प उम्मीदवार हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में 1904–05 के दौरान, जब जापानी साम्राज्य ने रूसी साम्राज्य को हराया, तो कई लोगों ने पश्चिमी शक्ति के खिलाफ एक पूर्वी शक्ति के उदय की घोषणा की, लेकिन तब तक जापान ने मीजी बहाली के तहत पश्चिमी तकनीकों और विकास मॉडल को पूरी तरह से अपना लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से, यह रणनीतिक रूप से पश्चिम के बहुत करीब रहा है। ऑस्ट्रेलिया, हालांकि अपने आप में एक महाद्वीप है, इतिहास और भू–राजनीति के माध्यम से, पश्चिम का एक दृढ़ सहयोगी बना हुआ है। हालांकि, गैर–पश्चिम के दो सबसे मजबूत स्तंभ एक–दूसरे के विरोधी हैं। चीन की सीमा पर आक्रामकता ने भारत–चीन संबंधों को हाल के समय में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा दिया हैय और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजिंग के अनियंत्रित उदय को रोकने के लिए वाशिंगटन के साथ एक मजबूत रणनीतिक सौदेबाजी करना नई दिल्ली के लिए और भी अधिक विवेकपूर्ण हो गया है। हालांकि, गैर–पश्चिम अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अभ्यास और अध्ययन के लिए पूरी तरह से नया नहीं है, हालांकि भारत और चीन जैसे देशों की स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों और उपनिवेशवाद के बाद के अनुभव में भौतिक घाटे ने इस तरह के आख्यानों को आगे बढ़ने नहीं दिया। एशियाई लोगों के लिए एशिया विकसित करने के आह्वान में, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (छप्म्), व्यापक कोर–परिधीय प्रश्न, भारत और चीन के आर्थिक उदय पर आधारित एक एशियाई सदी के लिए शुरुआती आशावाद और नवीनतम वैश्विक दक्षिण अनिवार्यता के माध्यम से, गैर–पश्चिम ने कई अवतारों में खुद को प्रतिध्वनित किया है। दबावपूर्ण समस्याएँ हालाँकि, विभाजित एशिया और बहुध्रुवीय दुनिया में एकध्रुवीय एशिया को आकार देने की चीन की अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं ने किसी भी एकजुट एशियाई सदी या कम से कम नीतियों और रणनीतियों की वास्तविक दुनिया में व्यवहार्य गैर–पश्चिम की संभावनाओं के खिलाफ बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं, अगर अकादमिक चर्चा में नहीं। पश्चिम और गैर–पश्चिम का द्वंद्व उत्तर–दक्षिण संवाद और वैश्विक दक्षिण के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में उभरने में भी स्पष्ट रूप से व्याप्त है, जिसे सतत विकास और विकास की आवश्यकता है। विभाजित एशिया और एकध्रुवीय एशिया को आकार देने की चीन की अत्यधिक महत्वाकांक्षाओं ने व्यवहार्य गैर–पश्चिम के खिलाफ बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं भारत की जी–20 अध्यक्षता का उच्च बिंदु वैश्विक दक्षिण की चिंताओं और आवश्यकताओं की पैरवी करना था, लेकिन सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लक्ष्यों को उत्तर–दक्षिण सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जाना चाहिए, न कि विरोधों को और आगे बढ़ाकर। बहुपक्षीयता में सुधार और बहुध्रुवीय विश्व के लिए बहुपक्षीय संस्थाओं को आकार देने की अनिवार्यता का अर्थ है कि शासन के वैश्विक और क्षेत्रीय मंचों पर पश्चिम का पूर्व वर्चस्व अधिक समावेशी समाधानों की खोज का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जलवायु परिवर्तन और हरित अर्थव्यवस्था, वैश्विक खाद्य और स्वास्थ्य सहित भविष्य की सबसे गंभीर समस्याएं नई महाशक्तियों के बीच बढ़ती भू–राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बीच, गैर–पश्चिम और पश्चिम के बीच तालमेल बनाने के लिए, सुरक्षा, लचीली मूल्य आपूर्ति श्रृंखला और नई प्रौद्योगिकियों के प्रबंधन के लिए अधिक ठोस प्रयास की आवश्यकता होगी। गैर–पश्चिम में एक भौतिक और मानक शक्ति के रूप में भारत का उदय ऐसे समय में हुआ है जब गैर–पश्चिम में अपनी सुरक्षा चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए पश्चिम को गले लगाना व्यावहारिक लगता है।

जलालपुर पुलिस ने चार शातिर चोरों को मोटर साइकिल दो मोटर पम्प के साथ किया गिरफ्तार

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के रेहटी गांव के पास से पुलिस ने चार शातिर चोरों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। पुलिस अधीक्षक डॉ0 अजय पाल शर्मा द्वारा अपराध व अपराधियों विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में थाना प्रभारी जलालपुर मनोज कुमार सिंह, के निर्देशन पुलिस ने चार चोरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि शिवम प्रजापति उर्फ बाबा पुत्र प्रकाशचन्द निवासी ग्राम मोजरा थाना जलालपुर, प्रदीप उर्फ बिल्डर पुत्र छोटेलाल पटेल निवासी ग्राम मेघपुर थाना जलालपुर, प्रदीप कुमार पुत्र जयकुमार निवास ग्राम पुरेव थाना जलालपुर अभय पटेल पुत्र

जियालाल नि0 लोहगाजर थाना जलालपुर, जिनकी निशानदेही पर एक मोटर साइकिल लूट की व एक आयसर कम्पनी का मोटर पम्प व एक किर्लोस्कर इन्जन मोटर पम्प चोरी की बरामदगी की गयी ।

पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा जेल

उक्त लूट व चोरी के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0– 214/24 धारा 309(3), 317(2) बी0एन0एस व मु0अ0सं0– 215/24 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 व मु0अ0सं0– 216/24 309(5) बी0एन0एस0 व मु0अ0सं0– 217/24 धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना जलालपुर, जौनपुर का अभियोग पंजीकृत है। उपरोक्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व बरामदगी के पश्चात् नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पीड़ित की फरियाद सुनते सुनते दरोगा की मौत हुई

अयोध्या। किसी भी व्यक्ति की मौत कब और कहां आ जाये किसी को पता नहीं। इसका जीता–जागता उदाहरण गुरुवार को उस समय दिखाई दिया जब कोतवाली अयोध या क्षेत्र के नया घाट चौकी पर फरियादियों की शिकायतों का निस्तारण करते समय उप निरीक्षक सुरेंद्रनाथ त्रिवेदी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मृतक दरोगा सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी अयोध्या कोतवाली में तैनात थे। जो कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के नयाघाट चौकी पर फरियादियों की सुन रहे थे कि इसी बीच उसी बीच उनकी अचानक तबियत बिगड़ गई।पुलिस ने उक्त दरोगा को आनन फानन में श्री राम अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना की सूचना पुलिस ने तुरंत मृतक दरोगा के परिजनों को दी। मृतक उप निरीक्षक सुरेंद्रनाथ त्रिवेदी ग्राम सदरपुर थाना बिलग्राम जनपद हरदोई का निवासी बताया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी।

द्वितीय जिला स्तरीय योगासन प्रतियोगिता संपन्न

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। एक तरफ जहां प्रदेश सरकार बच्चों की सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद और योग क्रिया को बढ़ावा दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट संस्थानों द्वारा भी योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के तहत योगासन स्पोर्ट्स एलाइंस एसोसिएशन के तत्वाधान में नगर के शिया डिग्री कॉलेज में जिला स्तरीय द्वितीय योगासन खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट अतिथि एमएलसी बृजेश कुमार सिंह प्रिशु द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों द्वारा अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 200 छात्र–छात्राओं ने योग क्रिया का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खेलकूद राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव व नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मनोरमा मौर्य व डॉ वीएस उपाध्याय द्वारा प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। निर्णायक मंडल में राष्ट्रीय स्तर की रेफरी आदित्य लंबा निशांत पंवार अभय देशवाल हिमांशु गुप्ता कार्तिक गौरव वेदवान रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से योगा फेडरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आचार्य भीम जी सहकार भारती के अध्यक्ष प्रदीप सिंह रिंकू संस्कार भारती के महामंत्री अमित गुप्ता महामंत्री पीयूष गुप्ता क्षेत्रीय विपणन अधिकारी अनिल गुप्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नारायण चौरसिया भाजपा नगर अध यक्ष अमित श्रीवास्तव आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इससे पूर्व योगा एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी डाली गुप्ता सेक्रेटरी मधु गुप्ता कोषाध्यक्ष रचित साहू व इंदिरा जायसवाल द्वारा आए हुए अतिथियों का बैच लगाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आए अतिथियों को संस्था द्वारा स्मृति चिन्ह भेट कर सम्मानित किया गया। कार्यकम में विशेष रूप समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह, शिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ सैय्यद अमलदार हुसैन रौनक साहू ,रत्नेश शर्मा ,अजय गुप्ता अमित जी वैश्य ,संजीव साहु रजनीश गुप्ता संदीप गुप्ता आदि का विशेष सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के अंत में योगा फेडरेशन की अध्यक्ष रजनी साहू व रामजी ने सभी अतिथियों विशिष्ट अतिथियों व कार्यक्रम में भाग लेने आए सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन अनुष्का साहू इशिका सिंह ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के संयोजक रामजी सुतरी वाले रहे।

डा. राजकुमार बने पीयू के मानद पुस्तकालय अध्यक्ष

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय का मानद पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर

इंजीनियरिंग संस्थान के गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजकुमार को नियुक्त किया गया है। कुलपति प्रो. वंदना सिंह के आदेश पर इस आशय का पत्र कुलसचिव कार्यालय से मंगलवार को जारी किया गया है। गुरुवार को प्रो. राजकुमार ने लाइब्रेरियन पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। कार्यभार लेने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी के सभी कर्मचारियों के साथ गुरुवार को औपचारिक बैठक की। उन्होंने सभी कर्मचारियों से परिचय प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने कर्मचारियों का कार्य पद्धति पर कुछ निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि लाइब्रेरी में बच्चे और शिक्षक नियमित आएं। इसे अपडेट करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसके पूर्व इस पद पर प्रबंध अध्ययन संकाय के प्रो. मानस पांडेय थे। डॉ. राजकुमार इसके पूर्व चीफ वार्डेन, प्राक्टर, मीडिया प्रभारी समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र के नोडल अधिकारी का भी प्रभार उनके पास है। विश्वविद्यालय के कार्य परिषद और विद्या परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। वह विश्वविद्यालय में 2004 से सेवारत हैं। प्रो. राजकुमार के मानद पुस्तकालय अध्यक्ष बनने पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने बधाई दी है।

तू जिन्दा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अवध प्रांत के अध्यक्ष एवं कानपुर प्रांत के संगठन मंत्री मेजर वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जय हिन्द साथियों मुझे बताते हुऐ गर्व ध्फक्र महसूस हों रहा है कि भारतीय सेना का जवान चाहे सर्विस में हो या रिटायर हो गया हो उसकी जिंदादिली हमेसा बरकरार रहती है. इसी को चरितार्थ करते हुऐ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अवध प्रान्त के महासचिव Sub Major. JBS Chauhan एवं लखनऊ पूर्वी भाग के संयोजक कैपटन बी. एस. कन्याल जी तथा वारंट ऑफिसर पूरन सिंह जी के द्वारा संचालित एकश पेड माँ के नाम श्के साथ गायत्री पार्क, कल्याण पुर लखनऊ में एकृतित होकर वृक्षारोपड़ किया साथ ही आगे इसके रखरखाव का भी संकल्प लिया गया। पूर्वी भाग के हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक भाइयों ने बड़े ही जोशो खरोस के साथ हिस्सा लिया. सभी के फोटो नीचे दिये गये हैं।

तू जिन्दा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसी प्रकार आगे मिलते रहेंगे. जय हिन्द....

बजट को सत्तापक्ष ने विकासोन्मुखी तो विपक्ष ने बताया भटका हुआ, केंद्रीय बजट पर लगी रही निगाहें, देखा गया सीधा प्रसारण

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सत्तारूढ़ एनडीए सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय आम बजट पेश किया। उन्होंने अपने बजट भाषण में महिलाओं, युवाओं व किसानों के उत्थान पर जहां विशेष ध्यान दिए जाने का दावा किया वहीं विकसित भारत के लक्ष्य को समय रहते हासिल कर लेने का भरोसा दिलाया। केंद्रीय बजट में मुद्रा लोन की सीमा को दोगुना करके बीस लाख किया गया तो शिक्षा के लिए ऋण की व्वयस्था में भी दरियादिली दिखाई गई। किसानों के जीवन को आसान बनाने का भी वित्त मंत्री ने जज्बा दिखाया। मोबाइल फोन, चार्जर जैसी जन सामान्य से जुड़ी अन्य चीजों पर भी ठर राहत की घोषणा की गई। केंद्रीय बजट को जानने समझने के लिए लोग न्यूज चौनलों के सामने बैठे रहे। केंद्रीय बजट को जहां सत्तापक्ष से जुड़े लोगों ने जन हितैषी व विकसित भारत का रोडमैप बताया वहीं विपक्ष के लोगों ने जनविरोधी व भटका हुआ करार दिया। शिक्षकों–कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना पर सरकार की चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण व निराशाजनक कहा। विपक्षी नेताओं ने बजट पर तंज कसा कि यूपी जैसे बड़े राज्य की उपेक्षा की गई है। कुछ राज्यों के विकास के लिए जहां लालीपाप दिखाया गया है वह वहां का विकास कम अपनी सरकार को बचाने की कवायद अधिक दिखलाई पड़ रही है।

सत्ता पक्ष ने सराहा तो विपक्ष ने बजट पर कोसा

बजट पर भाजपा के जिलाध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने कहा कि बहुत अच्छा बजट रहा है। विकसित भारत की दिशा में बजट अग्रसर रहा। गरीबों ,नौजवानों, महिलाओ, किसानों के आकांक्षाओं के अनुकूल है। सपा जिलाध्यक्ष राकेश मौर्या ने कहा कि बजट निराशाजनक रहा। किसानों ,नौजवानों व महिलाओं को उम्मीद थी इस बार उनके लिए कुछ अलग होगा लेकिन बजट जनविरोधी रहा। जो कर्मचारी पेंशन के लिए आंदोलनरत है उनके लिए भी कुछ नही है। बसपा जिलाध्यक्ष संग्राम भारती ने कहा कि ये बजट लुभावने है। अपने पुराने ढर्रे पर है। सिर्फ अमीर लोगों के लिए गरीबों के लिए वंचित है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हुकुम सिंह ने कहा कि यह एक निराशाजनक बजट है। आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख था। जब बात गंभीर आय असमानता की आती है तो सरकार की ओर से हमें बहुत कम देखने को मिलता है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष डॉ प्रदीप सिंह ने कहा कि केंद्रीय आम बजट 2024–25 कर्मचारियों के लिए निराशाजनक एवं उम्मीद के विपरीत है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली तथा आठवें वेतन आयोग के गठन जैसे कर्मचारी हित के मुद्दों पर आश्चर्यजनक रूप से बजट बिल्कुल मौन है। इनकम टैक्स स्लैब में छूट अति सूक्ष्म है। जिसका प्रभाव नगण्य होगा। कर्मचारी शिक्षक समुदाय अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर पूरे देश में संघर्ष और तेज करेगा।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला मंत्री देवेश कुमार यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संसद में पेश हुआ आम बजट कर्मचारियों की आशा के अनुरूप नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली या एनपीएस में संशोधन,आठवें पे कमीशन तथा इनकम टैक्स स्लैब जैसे कर्मचारी हित के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। सरकार निजीकरण को बढ़ावा देने की तरफ अग्रसर है। हम लोग अन्याय के विरुद्ध आवाज बुलंद करेंगे।

जिला अधिकारी ने विभिन्न कार्यालय का किया आकस्मिक निरीक्षण नगर पालिका परिषद के एक कर्मचारी को किया सस्पेंड

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक व्यवस्था को स्वच्छ एवं पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए हैं ।इसके लिए सीधे पब्लिक से फीडबैक लिया जा रहा है कि कहीं किसी कार्यालय में कोई भ्रष्टाचार व्याप्त तो नहीं है और लोगों को किसी भी सरकारी कर्मचारियों को अपना काम करने के लिए पैसा ना देना पड़े ।इस उद्देश्य से गुरुवार को जिलाधिकारी रविंद्र कुमार सीडीओ एडीएम डीडीओ सी आर ओ व अन्य अधिकारियों द्वारा जिले के उप संभागीय परिवहन विभाग नगर पालिका परिषद, सदर तहसील, डूडा आफिस ,सीएमओ आफिस, आदि का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। साथ ही वहां पर मौजूद लोगों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्य के बारे में जिलाधिकारी द्वारा फीडबैक प्राप्त किया गया। अचानक इस कार्रवाई से कार्यालय में हड़कंप बच गया हालांकि जिलाधिकारी द्वारा निरीक्षण किए जाने के दौरान नगर पालिका परिषद के दो कर्मचारियों को कार्य मे लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया गया है। वही इस मामले में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मॉडेड ने बताया कि आज मैं स्वयं और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को लगाकर ऐसे विभाग जहां ज्यादा पब्लिक के लोग आते हैं जो वेलफेयर डिपार्मेंट है मुख्यमंत्री जी ने पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए निर्देश दिए हैं कि कहीं किसी कार्यालय में किसी सरकारी कर्मचारियों द्वारा किसी से काम के बदले में पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं कहीं भ्रष्टाचार ना हो लोग काम के लिए पैसे ना मांग रहे हो इसको देखने के लिए आज हम सभी लोग निकले थे सबसे पहले ए आर टी ओ विभाग गया जहां लगभग 50 लोगों से फीडबैक लिया लेकिन किसी ने भी सीधे तौर पर पैसे लेने की बात नहीं कही है लोगों के काम भी वहां पर हो रहे हैं इसके बाद नगर पालिका कार्यालय परिषद पहुंचा जहां एक फाइल के पेंडिंग के मामले की शिकायत मिली थी इस मामले में कर निर्धारण अधिकारी की शिकायत थी जो ऑफिस के लोगों ने बताया कि वह समय से नहीं आती हैं ठीक से काम भी नहीं करती हैं जिस कारण ज्यादा मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं। उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की जा रही है इसकी अतिरिक्त हमारे और भी अधिकारी सीडीओ, एडीएम, सीआरओ, लोगों ने भी ऑफिसों का निरीक्षण किया है मैं खुद तहसील का निरीक्षण किया है इस दौरान कहीं कोई लेखपाल या कानून के द्वारा पैसा मांगने की बात सामने नहीं आई है वहां उनके काम हो रहे हैं जो विधिक रूप से होने वाले काम न्यायालय के आदेश में है वह भी किया जा रहे हैं इस प्रकार औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे अभी सिटी मजिस्ट्रेट को सीएमओ ऑफिस का निरीक्षण करने के लिए भेजा गया है। तहसील ब्लाक थाने अस्पताल सीएमओ ऑफिस जहां पब्लिक आती है। वहां लगातार निरीक्षण किया जाता रहेगा उसमें कहीं किसी भ्रष्टाचार की व्यवस्था में लिप्त पाया गया पब्लिक का काम नही करते है तो हम लोग फिर उसमें सस्पेंशन या नौकरी जाने की कार्यवाही की जाएगी।

जज सिंह अन्ना का नहर में पानी को लेकर आमरण–अनशन समाप्त

एसडीएम सदर पवन, जेई नहर प्रवीन ने 12 बजे नहर में पानी खोलकर तुड़वाया अनशन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। क्रांतिकारी नेता जज सिंह अन्ना किसानों के हित के लिए शारदा सहायक खंड–39 नहर में पानी नहीं आने को लेकर 25 जुलाई गुरुवार को बेवुनियादी आमरण अनशन पर जिलाधिकारी कार्यालय धरना स्थल पर बैठ गए। जिलाधिकारी कार्यालय ने भी अपना सक्त रवैया अपनाते हुए लखनऊ सिचाई विभाग से आदेशित करवाया कि तुरंत नहर में पानी खोलिए । 3:00 बजे एसडीएम सदर पवन यादव और के नहर विभाग के जेई प्रवीण तिवारी ने धरना स्थल पर आकर जज सिंह अन्ना का आमरण अनशन तुड़वाया और कहां की नहर में पानी खोल दिया गया है फोटो और वीडियो देख लीजिए कई अधिकारियों की उपस्थिति में अन्ना ने उनकी बात मानकर अनशन तोड़ा। और कहां किया टेल तक पानी नहीं पहुंचा तो मैं फिर अनशन करूंगा। अधिकारियों ने कहा कि अगर अन्ना आमरण अनशन पर नहीं बैठते तो लखनऊ से पानी खोलने का आदेश नहीं आता और नहर में पानी खुलना संभव नहीं था। उपस्थित लोगों ने अन्ना का स्वागत करते हुए किसानों के हित में अन्ना की तारीफ की और अन्ना को आशीर्वाद दिया।

आईजीआरएस के मामलों का समय से करें निस्तारण शिकायतकर्ता से फोन से करें बात – अपर जिलाधिकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान एवं मुख्य राजस्व अधिकारी गणेश प्रसाद के उपस्थिती में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व वादों एवं आईजीआरएस के निस्तारण के संबंध में बैठक बुधवार देर सायं संपन्न हुई।

अपर जिलाधिकारी भू–राजस्व द्वारा समस्त राजस्व से संबंधित लंबित वादों की समीक्षा करते हुए शासन की मंशा के अनुरुप शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश दिया। उन्होंने धारा 24, 34, 80 और 116 के वादों के निस्तारण पर विस्तृत चर्चा करते हुए निर्देशित किया की अतिशीघ्र समस्त पुराने वादों का निस्तारण किया जाए। आईजीआरएस के समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों को ससमय निस्तारित करते हुए प्रार्थी से दूरभाष पर वार्ता करते हुए शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में जानकारी अवश्य प्राप्त कर ले, प्राप्त शिकायत किसी भी दशा में

डिफॉल्टर न होने पाए एवं ससमय गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन फीडबैक अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। इस अवसर पर नगर मजिस्ट्रेट इंद्र नंदन सिंह, उप जिलाधिकारीगण, तहसीलदारगण सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम सभी के लिए खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हैं – अर्चना पांडेय

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। सेंट गेब्रियल कान्वेंट स्कूल, केशव नगर, सीतापुर रोड,लखनऊ में आज संस्थापक दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस संस्थापक दिवस को 'अभिव्यक्ति' का नाम दिया गयाद्य अभिव्यक्ति का अर्थ विचारों के प्रकाशन से हैं। व्यक्तित्व के समायोजन के लिया मनोवैज्ञानिकों ने अभिव्यक्ति को मुख्य साधन माना हैद्य कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय प्रबंधक डा. विलियम अल्बर्ट स्मिथ द्वारा प्रार्थना से की। इस अवसर पर सभी कक्षाओं के बच्चों ने अपनी कलाओं को प्रदर्शित किया। किसी ने मॉडल, किसी ने क्राफ्ट इत्यादि बनायाद्य बच्चों द्वारा बनाये गए क्राफ्ट, मॉडलों को उपस्थित सभी अभिभावकों, शिक्षकों ने सराहा द्य सभी बच्चों ने कक्षा अध यापकों के मार्गदर्शन से अपनी अपनी कक्षाओं को खूबसूरत तरीके से अपनी कलाओं के माध्यम से सजाया द्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम सभी के लिए खुद को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हैं। विद्यालय प्रबंधक तथा निदेशिका द्वारा विद्यालय के नवनिर्मित कंप्यूटर कक्ष और प्री प्राइमरी बच्चों के लिए प्ले स्टेशन का उद्घाटन किया गया। विद्यालय निदेशिका सुश्री अर्चना पांडे ने बच्चों द्वारा बनाये गए क्राफ्ट, मॉडल इत्यादि चीजों की भरपूर सरहारना की। अंत में निदेशिका ने संस्थापक दिवस में आए सभी शिक्षकों, कर्मचारियों,बच्चों तथा अभिभावकों का आभार एवं धन्यवाद किया।

ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जी के मामा जी के निधन पर प्रदेश संगठन ने शोक व्यक्त कर दी श्रद्धांजलि

ब्यूरो चीफ आर एल पांडेय

लखनऊ। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सौरभ कुमार के छोटे मामा अनिल किशोर श्रीवास्तव अवकाश प्राप्त प्रोफेसर टाउन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बलिया डॉक्टर राममनोहर लोहिया के आई सी यू मे भर्ती थे. उनके फेफड़े मे संक्रमण हो गया था। अभी–अभी उनके निधन का समाचार मिला है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और परिजनों को दुःख सहन करने की क्षमता प्रदान करें।

खेत में ट्रैक्टर पलटने से किसान की दबकर मौत

कन्नौज, संवाददाता। कन्नौज जिले में खेत की जोताई करते हुए ट्रैक्टर का पहिया गड्ढे में जाने से पलट गया। हादसे में किसान की ट्रैक्टर में दबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। जेसीबी से ट्रैक्टर को हटाकर शव को बाहर निकाला गया। गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के समधन नगर के मोहल्ला सिकंदर नगर निवासी वासिद हुसैन (28) पुत्र आरिफ हुसैन खेती करते थे। परिजनों ने बताया कि बुधवार को वासिद अपने पड़ोसी का ट्रैक्टर लेकर खेत की जोताई करने के लिए गए थे। दोपहर करीब दो बजे खेत की जोताई करते समय ट्रैक्टर गड्ढे में जाने से पलट गया और वासिद ट्रैक्टर के नीचे दब गया। खेत की ओर गए बच्चों ने ट्रैक्टर पलटा देखा और शोर मचाया, जिसके बाद परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को हटाने का प्रयास किया, लेकिन ट्रैक्टर नहीं हटा सके। इसके बाद जेसीबी मशीन से ट्रैक्टर को हटाकर वासिद को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद परिजनों में चीख–पुकार मच गई। हादसे की जानकारी पर कानूनगो प्रेमशंकर मिश्रा, लेखपाल अतुल कुमार ने जांच की।

शासन से मुआवजा दिलाने की मांग

नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि अखलाक हुसैन, पूर्व अध्यक्ष प्रतिनिधि मुश्ताक अहमद, पूर्व अध्यक्ष नकीम खां, सपा नेता रफी अनवर सिद्दीकी, सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष गुफरान सिद्दीकी, अतीक हुसैन, बसपा नेता सैय्यद अहमद उसैब किसान के आवास पर पहुंचे। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए शासन से पीड़ित परिजनों को जल्द मुआवजा देने की मांग की है।

मां से कहासुनी के बाद बेटे ने फंदा लगा कर दी जान

इटावा, संवाददाता। कोई भी काम न करने पर मां की बेटे से कहासुनी हो गई। बेटे से नाराज होकर मां अपने मायके चली गई। दो दिन बाद बेटे ने फंदा लगाकर जान दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बिरारी गांव निवासी नेकराम (35) पुत्र तुलाराम ने घर के बरामदे में छत में लगे कुंडे में प्लास्टिक की रस्सी बांधकर जमीन पर कूलर रखकर उसके ऊपर चढ़कर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। बुधवार सुबह साढ़े छह बजे भतीजा विकास जब दादी के पेंशन के कागजात लेने के लिए चाचा के घर गया तब उसने दरवाजा खटखटाया। काफी देर तकर अंदर से कोई आवाज नहीं आने पर भतीजे ने रोशनदान से झांककर देखा तो चाचा फंदे पर लटके हुए थे। भतीजे ने चाचा को फंदे पर लटका देख चीखपुकार मचा दी। आवाज सुनकर पड़ोसियों के साथ परिवार के लोग पहुंचे। दरवाजे में जोर से धक्का मारने पर खुल गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक भीमसेन पौनिया ने फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य इकट्ठा कराए। रामदास ने बताया कि भाई नेकराम कोई काम नहीं करता था। मां सर्वती के काम करने को कहने पर दो दिन पहले कहासुनी हो गई थी। जिसके बाद गुस्से में मां अपने मायके गांव रमपुरा कुदरकोट चली गईं। नेकराम घर में अकेला था तभी मौका पाकर फंदे पर लटक कर खुदकुशी कर ली। तीन साल पहले उसकी पत्नी भी तलाक लेकर चली गई। भाई मानसिक रूप से तनाव में भी चल रहा था। पांच भाइयों में चौथे नंबर का था। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है। प्रभारी निरीक्षक भीमसेन पौनिया ने बताया कि युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। परिजनों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है।

खेल शिक्षक पर शारीरिक शोषण का आरोप लगा

कानपुर, संवाददाता। कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र के एक स्कूल के खेल शिक्षक पर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा 9वीं की छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया। आरोप है कि शिक्षक ने बहला फुसलाकर उसका अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका शोषण करने लगा। परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। चकेरी क्षेत्र की महिला के अनुसार वर्ष 2019 में उनकी बेटी एक विद्यालय में कक्षा नौ की छात्रा थी। वहीं के खेल शिक्षक ने बेटी का अश्लील वीडियो बना लिया। इसके बाद पांच साल से बेटी को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक शोषण कर रहा है। आरोपी की हरकतों से तंग आकर 14 जुलाई 2024 को बेटी ने आत्महत्या का प्रयास किया।

जब उन्होंने बेटी से पूछा तो उसने आपबीती बताई। हालांकि उन्होंने लोकलाज के डर से पहले तो आरोपी की शिकायत नहीं की, लेकिन आरोपी ने जब फोन कर फिर से वीडियो वायरल करने और परिवार को जान से मारने की धमकी दी तो उन्होंने चकेरी पुलिस से शिकायत की।

थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

सामाजिक कार्यकता की हत्या करने आए छह बदमाश गिरफ्तार, तमंचे व कारतूस भी बरामद

शामली, संवाददाता। कांधला थाना क्षेत्र के डूंडू खेड़ा ग्राम में सामाजिक कार्यकर्ता राजपाल की हत्या करने आए 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने एक बदमाश के पास से विदेशी पिस्टल व अन्य बदमाशों के पास से दो तमंचे व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया है। एसपी शामली रामसेवक गौतम ने जनपद में कावड़ यात्रा से कुशल संपन्न कराने को लेकर जनपद पुलिस को सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा–निर्देश दिए हैं। इसे लेकर चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चौकिंग अभियान के दौरान कांधला पुलिस ने मार्ग पर छह संदिग्ध लोगों को कार में जाते हुए देखा ।पुलिस ने उक्त लोगों को रोकने का इशारा किया तो बदमाशों ने कार लेकर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने मार्ग पर घेराबंदी कर बदमाशों को मौके पर ही दबोच लिया। पुलिस सभी बदमाशों को मौके पर गिरफ्तार करने के बाद थाने ले आई। पुलिस ने तलाशी के दौरान कब्जे से एक पिस्टल जिगाना, 10 कारतूस 9 एमएम प्रतिबंधित, एक तमंचा 315 बोर मय दो कारतूस 315 बोर व एक तमंचा 12 बोर व दो कारतूस 12 बोर व एक गाडी फ्रॉक्स नं0 एचआर 98आर 5700 बरामद हुआ है। आरोपियों ने पूछताछ पर बताया कि बीते रविवार की रात्रि में डुंडुखेड़ा निवासी राजपाल सिंह व ग्राम गढीरामकौर निवासी लोकेश पुत्र सतपाल के घटना किसी मामले को लेकर विवाद हो गया था। जिसके बाद उक्त् पक्ष राजपाल से रंजिश रखने लगा। गढ़ीरामकौर के लौकेश उर्फ लोकी पुत्र सतपाल के बुलाने उक्त लोग राजपाल की हत्या करने के लिए मौके पर आए थे। पुलिस पूछताछ के दौरान बदमाशों ने अपने नाम अनिल पुत्र जिलेराम निवासी उलावास थाना सैक्टर 65 गुरूग्राम जिला गुरूग्राम हरियाणा, विक्की पुत्र सूरजभान निवासी विकासपुरी मकान नं0 220 जे ब्लाक थाना विकासपुरी जनपद वैस्ट दिल्ली नई दिल्ली, विवेक उर्फ विक्की पुत्र वेदपाल निवासी बी 407 गंगानगर थाना गंगानगर जिला मेरठ, सचिन पुत्र करतार निवासी बरवन्तपुर थाना गुलावठी जिला बुलन्दशहर तथा अरूण कहराना पुत्र जितेन्द्र कहराना निवासी ग्राम कमाला थाना सिंघावली अहीर जिला बागपत, सूरज घामा उर्फ अमित पुत्र देवेन्द्र सिंह नि० बेहटा हाजीपुर राजनगर 250/26एफ थाना लोनी बोर्डर जिला गाजियाबाद बताया है। विदेशी पिस्टल के साथ बदमाशों को पकड़े जाने के बाद से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हरकत में है। घटना के संबंध में एटीएस सहित कई टीमें पूछताछ में जुटी है। सीओ कैराना अमरदीप मौर्य का कहना है कि विदेशी पिस्टल कहां से खरीदी गई, और प्रतिबंधित हथियार से क्या–क्या घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा इसकी जांच की जा रही है।

नौकरी का झांसा देकर 1.45 लाख रुपये हड़पे, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज

फतेहपुर, संवाददाता। नौकरी का झांसा देकर युवक को टूरिस्ट वीजा पर दुबई भेज दिया। फर्जीवाड़े का अहसास विदेश पहुंचने के बाद हुआ। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। राधानगर थाना के गांव रमवां पंथुवा निवासी संदीप ने बताया कि वह विदेश में नौकरी करना चाहता था। गांव के विनोद ने पंजाब प्रांत के अमृतसर गांव फतेहगढ़ रसूलपुर निवासी एजेंट सुखवीर के माध्यम से वीजा बनवाकर विदेश भेजने की बात कही। विनोद ने एजेंट को गांव भी बुलवा लिया। सात अक्तूबर 2022 को सुखवीर के खाते में 24,500 और 25,000 रुपये दो बार में भेजे गए। इसके पहले वह एप के माध्यम से दो बार 20–20 हजार और एक बार 10,000 रुपये एजेंट सुखबीर के पास भेजा चुका था। विनोद और सुखबीर सिंह के कहने पर नौ मई 2023 को वह अमृतसर पहुंचा। वहां टिकट व टूरिस्ट वीजा देकर दुबई की फ्लाइट में बैठा दिया। उसे दुबई में कोई काम नहीं मिला। सुखवीर से फोन पर काम न मिलने की बात बताई, तो उसने गाली–गलौज किया। संदीप ने बताया कि मिन्नतों के बाद उसे वतन वापस बुलाया। लेकिन 1,45,500 रुपये नहीं लौटाए। शिकायत पर पुलिस के एफआईआर दर्ज नहीं की। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर राधानगर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

मजदूरों से भरी बस पलटी, कई मजदूर घायल हो गए

सहारनपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के देवबंद में मंगलवार को देर रात लगभग डेढ़ बजे स्टेट हाईवे पर हादसा हो गया। यहां साखन नहर के पास एक मजदूरों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई जिसमें कई मजदूरों को मामूली चोटे आई हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का देवबंद के सरकारी अस्पताल में उपचार कराया। जहां से सभी को मरहम पट्टी के बाद छूट्टी दे दी गई। जिसके बाद सभी को दूसरी बस द्वारा उनके गंतव्य की और भेज दिया गयाहै। मंगलवार को देर रात लगभग डेढ़ बजे एक मजदूरों से भरी हुई बस नेपाल से शिमला जा रही थी। जैसे ही वह स्टेट हाईवे साखन नहर के पास जेन रेस्टोरेंट के पास पहुंची तो बस चालक को नींद की झपकी आ गई जिसकी वजह से बस अनियंत्रित होकर बराबर गहराई में उतर कर पलट गई। जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बाहर निकाल घटना में रेशम कुमार पुत्र प्रेम बहादुर, टीकाराम पुत्र रतनलाल,अरमत भंडारी पुत्र दीप्पा, प्रभात पुत्र बाल्ला, चन्द्र मल्ला पुत्र कर्क सिंह, मीना पत्नी नोला सिंह ममता पत्नी चन्द मल्ला,कालिका पुत्र टंकराज को एम्बुलेंस की मदद से देवबंद के सरकारी अस्पताल में भिजवाया गया, जहां से मरहम पट्टी के बाद सभी की छुट्टी कर दी गई थी। इसके बाद सभी को दूसरी बस से उनके गंतव्य की ओर भेज दिया गया है।

रास्ते पर कब्जे से भड़कीं महिलाओं ने जाम किया हाईवे, रोकी एंबुलेंस

हमीरपुर, संवाददाता। हमीरपुर जिले में भरुआ सुमेरपुर कस्बे के वार्ड संख्या एक में निकलने वाले रास्ते की जमीन पर कब्जा करके सीसी मार्ग का निर्माण कार्य रोकने से नाराज महिलाओं ने बांदा मार्ग (स्टेट हाईवे) पर जाम लगा दिया। इस दौरान वहां से गुजर रही एंबुलेंस को भी महिलाओं ने रोक लिया। जिसे रास्ता दिलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस की सख्ती के बाद एंबुलेंस को रास्ता मिल सका। महिलाओं को समझाने के एक घंटे बाद जाम खुल सका। कस्बे के वार्ड संख्या एक की निवासी सुनीता निषाद, विद्या विश्वकर्मा, विजय लक्ष्मी, रानी, कमला, अनुसुइया, सुशीला, रजनी, सीता देवी, रामजानकी, कल्पना, रेखा, रामप्यारी सहित 100 से अधिक महिलाएं मामले को लेकर नाराज दिखीं। उन्होंने बताया कि एक रास्ता बस्ती से होकर सीधे बांदा मार्ग पर जुड़ता है। आरोप है कि बांदा मार्ग के किनारे रहने वाले मुन्ना विश्वकर्मा ने रास्ता बंद करके सीसी मार्ग का निर्माण रोक दिया है। इससे बस्ती के लोग परेशान हैं। इसी से नाराज महिलाएं दोपहर करीब तीन बजे बांदा मार्ग जाम करके हंगामा करने को मजबूर हो गईं। इस दौरान महिलाओं के साथ आए छोटे बच्चे भी हाईवे पर बैठक गए।

उधर, जाम की सूचना पाकर क्राइम इंस्पेक्टर रामकुमार यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रभारी अधिशासी अधिकारी से फोन पर वार्ता कर उन्हें समस्या से अवगत कराया। महिलाओं द्वारा बांदा स्टेट हाईवे पर जाम लगाने के दौरान एक एंबुलेंस बीच में फंस गई। इसको निकलवाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। क्राइम इंस्पेक्टर ने जब महिलाओं से एंबुलेंस निकलने के लिए सड़क से हटने के लिए कहा तो महिलाओं ने रास्ता खोलने से मना कर दिया। इस क्राइम इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी। तब कहीं जाकर महिलाओं ने एंबुलेंस को रास्ता दिया।समस्या के समाधान के लिए दोनों पक्षों को शनिवार को थाने पर बुलाया गया। क्राइम इंस्पेक्टर के समझाने पर महिलाओं ने जाम खोल दिया। एक घंटे तक जाम लगने से दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई।

अपहरण के बाद किशोरी की हत्या

मेरठ, संवाददाता। मेरठ से सटे सरधना में किशोरी की हत्या की बड़ी वारदात सामने आई है। नगर के मोहल्ला कुम्हारान में किशोरी की प्रेम प्रसंग में अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। किशोरी एक सप्ताह से लापता चल रही थी। नगर के मोहल्ला कुम्हारान निवासी किशोरी की प्रेम प्रसंग के चलते अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। थाना क्षेत्र के इकड़ी रोड पर मेहरमती गणेशपुर के जंगल में मिले महिला के शव की शिनाख्त हो गई है।

मृतक की पहचान मुस्कान पुत्र गुलजार निवासी मोहल्ला कुम्हारान के रूप में हुई है। परिजनों ने किशोरी की पहचान पैर पर तिल व कपड़ो से की है। मृतक के परिजनों ने कस्बा निवासी आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

परिजनों को आरोप है कि एक सप्ताह पूर्व किशोरी की गुमदगी की सूचना कस्बा चौकी पर दी थी। लेकिन कस्बा चौकी ने गुमशुदगी दर्ज नहीं की और मामले को दबाए रखा। जिस कारण आरोपियों ने किशोरी का अपहरण कर हत्या की घटना को अंजाम दिया है। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया।

आठ साल बाद 440 बेसिक शिक्षकों की पदोन्नति निरस्त

सहारनपुर, संवाददाता। बेसिक शिक्षा विभाग में आठ वर्ष पहले हुई शिक्षकों की पदोन्नति शासन ने निरस्त कर दी है। हालांकि इनमें से 397 शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन शासन की कार्रवाई से विभाग में खलबली मची है। विभागीय अधिकारी जवाब तैयार करने में जुटे हैं। इसके लिए पदोन्नति समिति की बैठक भी बुलाई गई है। दरअसल, वर्ष 2016 में जनपद में 440 शिक्षकों की पदोन्नति हुई थी। यह पदोन्नति प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की थी, जिन्हें उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर पदोन्नत किया गया था। तभी से इस पर जांच चल रही है। अब शासन ने पदोन्नति को वरिष्ठता में गड़बड़ी होने की बात कहते हुए निरस्त किया है, साथ ही उस समय रहे पटल लिपिक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर भेजने को कहा है, जिससे कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हो सके, लेकिन विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पदोन्नति पूरे नियमों के अनुरूप हुई थी। पदोन्नति समिति की देखरेख में पदोन्नति की प्रक्रिया अपनाई गई थी। शासन ने किस आधार पर इसे निरस्त किया है यह समझ से परे है, लेकिन विभाग इसका जवाब तैयार कर रहा है। इसके लिए पदोन्नति समिति की बैठक की जाएगी। जरूरत पड़ी तो विभाग कोर्ट भी जाएगा। करीब आठ वर्ष पहले 440 शिक्षकों की पदोन्नति हुई थी, जिसे शासन ने निरस्त कर दिया है। यह अलग बात है कि इनमें से करीब 397 शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और केवल 43 शिक्षक बचे हैं, लेकिन हम अपनी ओर से जवाब बना रहे हैं। समिति सदस्यों के साथ बैठक की जाएगी।

विहिप व बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दूसरे दिन भी किया प्रदर्शन,बदसलूकी पर थानाध्यक्ष व दो सिपाही लाइनहाजिर

बांदा, संवाददाता। बांदा जिले में पुलिस की बदसलूकी से गुस्साए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को भी बाइक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। एसपी कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्ता कथित मारपीट और अभद्रता के दोषी पुलिस कर्मियों के निलंबन और रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग कर रहे थे। इस पर एसपी ने तिंदवारी थानाध्यक्ष और दो सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच सीओ सदर करेंगे। तिंदवारी थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी का दूसरे समुदाय के युवक ने अपहरण कर लिया था। पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को खोज लिया था। इसकी जानकारी विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ताओं को हुई तो मंगलवार को तिंदवारी थाने पहुंच गए और धर्मांतरण व अन्य धाराओं में कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि थानाध्यक्ष राधा कृष्ण तिवारी ने उनके साथ अभद्रता की। इस पर कहासुनी हो गई।

थाना प्रभारी ने विहिप जिला मंत्री दीपू दीक्षित और बजरंग दल के जिला संयोजक केपी प्रजापति को पीट दिया। उनके गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला भी छीनकर फेंक दी। इस पर कार्यकर्ताओं ने देर रात एसपी आवास का घेराव किया था।

दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। देर रात एएसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने सीओ सदर अजय कुमार सिंह को जांच की जिम्मेदारी सौंपी थी।

उधर, दूसरे दिन बुधवार को भी विहिप व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर में बाइक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। एसपी कार्यालय का घेराव किया।

संक्षिप्त खबरें

दरोगा पर रिश्वत मांगने का आरोप

फर्रुखाबाद, संवाददाता। फर्रुखाबाद जिले में मानहानि के मुकदमे में आख्या लगाने के नाम पर युवक ने दरोगा पर दस हजार रुपये मांगने का आरोप लगाया है। बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर कोतवाली के मोहल्ला नितगंजा निवासी एक युवक ने मोहल्ले के अमित शुक्ला के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था। कोर्ट ने इस संबंध में शहर कोतवाली पुलिस से आख्या मांगी थी। एसओ जेपी शर्मा ने आख्या देने के लिए घुमना चौकी इंचार्ज आशु को आदेश दिए थे। चौकी इंचार्ज ने आख्या कोर्ट में भेज दी। चौकी पर दूसरे दरोगा विभूति प्रसाद की भी तैनाती है। वादी युवक का विभूति प्रसाद से बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वादी युवक ने विभूति प्रसाद पर दस हजार रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। रुपये नहीं देने पर कोर्ट में भेजी आख्या में युवक के खिलाफ रिपोर्ट लगा दी। एसओ जेपी शर्मा ने बताया कि आरोप निराधार है। वादी युवक का अमित शुक्ला से विवाद चल रहा है। आख्या मनमाफिक नहीं देने पर आरोप लगाए गए हैं।

ताजमहल में जलाभिषेक के लिए याचिका दायर

आगरा, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के आगरा में मंगलवार को अदालत में एक याचिका दायर की गई है। याचिका योगी यूथ ब्रिगेड ने लघुवाद न्यायाधीश मृत्युंजय श्रीवास्तव की अदालत में दायर की। याचिका में सावन महीने में ताजमहल में जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक की मांग की है। याचिका में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. राजकुमार पटेल को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता कुंवर अजय तोमर ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने एएसआई अधीक्षण पुरातत्वविद को समन और नोटिस जारी करने के आदेश दिए।

याचिकाकर्ता योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर का कहना है कि ताजमहल यानी तेजोमहालय भगवान शिव का मंदिर है। इसमें जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक होना चाहिए। ताजमहल में उर्स का आयोजन होता है तो फिर जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक क्यों नहीं हो सकता ?

अनुपस्थित एक्सईएन व नेडा अधिकारी से मांगा स्पष्टीकरण

बांदा, संवाददाता। मंडलायुक्त ने मंगलवार को विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा की। विकास कार्यों की बिंदुवार जानकारी ली। अधिकारियों से समय पर कार्यालय पहुंचने और बैठकर जनसमस्याएं सुनने को कहा। बैठक में अनुपस्थित जल निगम एक्सईएन और नेडा के मंडलीय अधिकारी से तीन दिन में स्पष्टीकरण मांगा। कार्यालय सभागार में आयुक्त बालकृष्ण त्रिपाठी ने कहा कि तेज गति से विकास कार्य कराएं। अधिकारी मासिक लक्ष्य हर हाल में पूरा कराएं। सड़कों का निर्माण व मरम्मत में गुणवत्ता का ध्यान रखें। पीएम आवास योजना में धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की। बिजली विभाग के अधिकारियों से लाइन लॉस कम कराने व खराब ट्रांसफार्मरों को समय से बदलवाने, विद्युत बिलों में समय से सुधार के निर्देश दिए। बैठक में डीएम नगेंद्र प्रताप, चित्रकूट डीएम शिवशरण अप्पा जीएन, डीएम हमीरपुर राहुल पांडेय, अपर आयुक्त प्रशासन अमर पाल सिंह, संयुक्त विकास आयुक्त यशवंत कुमार सिंह उपस्थिति रहे।

बाइक टकराने से नाराज कांवड़ियों का हंगामा, जीजा–साले को जमकर पीटा

सहारनपुर, संवाददाता। सहारनपुर जनपद के गागलहेड़ी में बाइक की टक्कर से गंगाजल बिखरने से नाराज हरियाणा के कांवड़ियों ने जीजा साले को लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। उनकी बाइक में भी जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने कावड़ियों को गंगाजल देकर किसी तरह समझा बुझाकर गंतव्य के लिए रवाना किया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। पीड़ित युवक ने 7 कावड़ियों के खिलाफ तहरीर दी है। मंगलवार देर रात अमन पुत्र लीलू निवासी जमालपुर थाना जनकपुरी अपने जीजा मोनू निवासी गांव मच्छरहेड़ी के साथ गागलहेड़ी से सहारनपुर बाइक पर जा रहे थे। जैसे ही ये हिंडन पुल के समीप बजाज एजेंसी के सामने पहुंचे तो इनकी बाइक कांवड़ियों से टकरा गई। बाइक टकराने से कांवड़िये की कावड़ में रखा गंगाजल बिखर गया। इससे नाराज कांवड़ियों ने दोनों युवकों के साथ मारपीट करते हुए बाइक को लाठी डंडों से तोड़कर क्षतिग्रस्त दिया। मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि अमन को भी चोटें आई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने थाने में रखा गंगाजल मंगा कर कांवड़ियों को देते हुए समझाबुझा कर मामला शांत कराया। पुलिस ने बाइक सवारों को कांवड़ियों के चंगुल से छुड़ाते हुए गंभीर रूप से घायल मोनू को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया।

ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में छोड़ दिया तौलिया

औरैया, संवाददाता। अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने महिला के पेट में तौलिया छोड़ दिया। ऑपरेशन के बाद भी महिला को पेट में असहनीय दर्द रहने लगा। परिजनों ने कानपुर में एक अस्पताल में ऑपरेशन कराया तो पेट से तौलिया निकला। रुरुगंज क्षेत्र के गांव चंदैया निवासी अवधेश कुमार राजपूत बिधूना में डॉ. लोहिया हॉयर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल लोहिया नगर में प्राइवेट शिक्षक हैं।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।